परिसीमन पर न करें जल्दबाजी : खड़गे

खड़गे ने 543 सीटें ही रखने लिखा पीएम को पत्र

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 28 अगस्त. लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर सियासी बहस एक बार फिर तेज हो गई है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर परिसीमन से जुड़े किसी भी प्रस्ताव पर आगे बढ़ने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है.

उन्होंने कहा कि यह देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण विषय है और इस पर जल्दबाजी में निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए. कांग्रेस अध्यक्ष का यह पत्र संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बयान के बाद आया है. रिजिजू ने संसद की एक और बैठक या विशेष सत्र की संभावना से इनकार नहीं किया था.

खड़गे ने पत्र में कांग्रेस का रुख भी स्पष्ट किया. पार्टी लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या को अगले 25 वर्षों तक बनाए रखने के पक्ष में है. इसके साथ ही कांग्रेस चाहती है कि राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का मौजूदा अनुपात भी इसी अवधि तक बरकरार रहे. कांग्रेस ने 2029 के लोकसभा चुनाव से महिलाओं के लिए लोकसभा में एक-तिहाई सीट आरक्षित करने की मांग भी दोहराई है.

सर्वदलीय सहमति जरूरी

पार्टी का कहना है कि परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर सभी पक्षों के बीच सहमति और विस्तृत चर्चा जरूरी है. पत्र में सभी राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों को सरकार के प्रस्ताव को समझने और उस पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय मिलना की बात कही है. उन्होंने याद दिलाया कि वह 16 जुलाई को भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इसी मुद्दे पर सभी दलों की बैठक बुलाने की मांग कर चुके हैं.

परिसीमन बिल पर सही समय और समर्थन का इंतजार

दो दिन का सत्र बुला सकती है सरकार

मानसून सेशन में मोदी सरकार परिसीमन विधेयक पेश नहीं कर पाई थी. अब इसे लेकर विशेष सत्र बुलाया जा सकता है. फिलहाल सरकार दो तिहाई नंबर जुटाने पर विचार कर रही है. इसके बाद सरकार संविधान संशोधन विधेयकों को पारित करने के लिए दो दिन का सत्र बुलाने पर विचार कर रही है. हालांकि इस बारे में अंतिम निर्णय तभी किया जाएगा, जब सरकार इन विधेयकों को पारित कराने के लिए आवश्यक दो तिहाई बहुमत के प्रति आश्वस्त हो जाए. सूत्रों के अनुसार आवश्यक संख्या बल जुटाने के लिए विपक्ष के कुछ दलों से बातचीत लगातार जारी है. 13 अगस्त को मॉनसून सत्र समाप्त होने के बाद दोनों सदनों को अनिश्चिकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है. लेकिन अभी तक संसद का सत्रावसान नहीं हुआ है यानी तकनीकी रूप से अब भी मॉनसून सत्र चल रहा है और दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी जब भी चाहें सदन की बैठक बुला सकते हैं. सरकार के कुछ वरिष्ठ मंत्रियों ने इशारा दिया है कि सरकार ने विशेष सत्र बुलाने का विकल्प खुला रखा है बल्कि मॉनसून सत्र के दौरान ही कुछ सांसदों से कह दिया गया था कि दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाएंगे, लेकिन सत्रावसान नहीं होगा. जानकारी सामने आई थी कि सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों को पारित कराने के लिए विशेष सत्र बुला सकती है. सरकार ने बजट सत्र में भी ऐसा ही किया था. तब सत्रावसान करने के बजाय 16 से 18 अप्रैल तीन दिनों के लिए विशेष सत्र बुलाया गया था. यह अलग बात है कि पूरी ताकत लगाने के बावजूद सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयकों को पारित नहीं करा सकी थी. हालांकि तब से लेकर अब हालात काफी बदल चुके हैं. डीएमके और टीएमसी सत्ता से बाहर हो गए.

लद्दाख में हाईकोर्ट बेंच को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

नवभारत नेटवर्क

लदाख, 28 अगस्त. लद्दाख के पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले आम नागरिकों और मुकदमों के मुवक्किलों के लिए न्याय पाना अब बेहद आसान और सुलभ होने जा रहा है.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख साझा हाई कोर्ट की नियमित बेंच (पीठ) के आयोजन का रास्ता पूरी तरह साफ कर दिया है. गुरुवार को राष्ट्रपति की ओर से जारी किए गए इस नए नियम के तहत अब लद्दाख के वादकारियों को सुनवाई के लिए श्रीनगर या जम्मू के चक्कर काटने से बड़ी राहत मिलेगी. यह निर्णय न केवल न्यायिक सुगमता की दिशा में एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव है, बल्कि सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों को उनके अधिकारों के प्रति सुरक्षा और कानूनी सशक्तिकरण का मजबूत भरोसा भी दिलाता है.

मुख्य पीठ में बदलाव नहीं

हाईकोर्ट की मौजूदा प्रधान पीठ में कोई बदलाव नहीं होगा. मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार भी होगा कि वे लद्दाख से संबंधित किसी भी मामले को श्रीनगर या जम्मू में सुनवाई के लिए निर्देशित कर सकें.

ट्रंप ने बदला ओंटारियो झील का नाम

कनाडा के साथ व्यापार वार्ता विफल होने से चिढ़े राष्ट्रपति

नवभारत नेटवर्क

वाशिंगटन, 28 अगस्त. कनाडा के साथ व्यापार वार्ता विफल होने से चिढ़े अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप. उन्होंने ओंटारियो झील (लेक ओंटारियो) का नाम बदलकर अमेरिका झील (लेक अमेरिका) कर दिया है.

इस संबंध में एक कार्यकारी आदेश पर ट्रम्प ने हस्ताक्षर कर दिए. उन्होंने कहा कि यह बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू होगा. कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के कार्यालय ने इस घटनाक्रम पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है.

कार्यकारी आदेश में आंतरिक विभाग और उसके मंत्री डग बर्गम को यह बदलाव करने का निर्देश दिया गया है. उत्तरी अमेरिका की पांच बड़ी झीलों में से एक ओंटारियो झील कनाडा के ओंटारियो प्रांत और अमेरिका के न्यूयार्क राज्य के बीच में स्थित है. दोनों देशों की सीमा इस झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों के बीच पानी से होकर गुजरती है. अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापार वार्ता पिछले हफ्ते विफल हो गई थी और दोनों पक्षों ने तीन दिनों की गहन बातचीत के पटरी से उतरने के लिए एक-दूसरे को दोषी ठहराया था. ट्रंप ने विश्वास जताया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किसी भी नाटो देश पर हमला नहीं करेंगे. उन्होंने उन मीडिया रिपोर्टों को ज्यादा अहमियत नहीं दी जिनमें कहा गया था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआए के निदेशक जॉन रैटक्लिफ ने इस हफ्ते की शुरुआत में रूसी अधिकारियों को ऐसे किसी हमले के विरुद्ध चेतावनी दी थी.

भाजपा ने पुलिस को राक्षस बनाया : ममता

- अभिषेक ने भी साधा निशाना, कहा- युवाओं की ताकत के आगे दिल्ली झुकी

नवभारत नेटवर्क

कोलकाता, 28 अगस्त. पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने राज्य की सत्तारूढ़ भाजपा सरकार और पुलिस प्रशासन पर करारा हमला बोला है.

ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी के शासनकाल में पुलिस का चेहरा मानवीय था, लेकिन भाजपा ने सत्ता में आते ही पुलिस बल को एक 'राक्षस' में बदल दिया है. ममता ने रक्षाबंधन के मौके पर अपने कार्यकर्ताओं से संकल्प लेते हुए कहा कि वह टीएमसी समर्थकों पर हो रहे पुलिसिया अत्याचारों को हर हाल में रोकेंगी. उन्होंने भाजपा पर पश्चिम बंगाल में विभाजनकारी राजनीति करने और लोगों के बीच खौफ फैलाने के लिए पुलिस बल का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया. राज्य में टीएमसी नेताओं पर हो रहे कथित हमलों पर निशाना साधते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने एलान किया कि वह जल्द ही पूरे पश्चिम बंगाल का दौरा शुरू करेंगी. अगर प्रशासन उनकी जनसभाओं की अनुमति नहीं देता है, तो वह सड़कों पर पैदल मार्च करेंगी. ममता ने कहा, 'मैं भी देखना चाहती हूं कि उनके पास कितनी ईंटें और अंडे जमा हैं.' उन्होंने कहा कि रैलियों की अनुमति के लिए वह बार-बार अदालत का दरवाजा खटखटाकर कोर्ट का समय बर्बाद नहीं करना चाहतीं.

यूएस में अब इंटर्नशिप करना भी छात्रों को होगा मुश्किल

- विदेशी छात्रों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी

वॉशिंगटन, 28 अगस्त. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन अंतरराष्ट्रीय छात्रों को मिलने वाली कुछ इंटर्नशिप कार्य-अनुमतियों पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

विश्वविद्यालयों को भेजे गए एक संघीय ज्ञापन में कुछ इंटर्नशिप से संबंधित अनुमति प्रक्रियाओं पर सख्ती करने की बात कही गई है. सरकार ने संकेत दिया है कि नियमों का पालन नहीं करने वाले शैक्षणिक संस्थानों की विदेशी छात्रों को दाखिला देने की मान्यता पर कार्रवाई हो सकती है. 24 अगस्त को जारी संघीय ज्ञापन में अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट के अंतर्गत आने सीपीटी से जुड़ी अनुमतियों में बढ़ोतरी का उल्लेख किया. ऐसी कुछ मंजूरियां नियामकीय शर्तों के अनुरूप नहीं दिखाई दे रही हैं. सीपीटी की अनुमति तभी दी जा सकती है, जब संबंधित प्रशिक्षण छात्र के स्थापित पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा हो.

प्रोटोकॉल तोड़ मंत्रियों के साथ बैठे विजय

पहली बार कोई सीएम अपने स्थान से अलग बैठे

नवभारत नेटवर्क

चेन्नई, 28 अगस्त. तमिलनाडु विधानसभा में गुरुवार को असामान्य नजारा देखने को मिला. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय अपनी निर्धारित सीट छोड़कर मंत्रियों के बीच जाकर बैठ गए.

विधानसभा के इतिहास में यह पहली बार है कि जब किसी मुख्यमंत्री ने अपनी तय सीट छोड़कर मंत्री के लिए निर्धारित सीट पर बैठकर कार्यवाही में हिस्सा लिया. वे सदन के नेता और मंत्री केए सेंगोट्टैयन और मंत्री आधव अर्जुन के बीच जाकर बैठ गए. मुख्यमंत्री के लिए विधानसभा में स्पीकर की सीट के पास अलग सीट निर्धारित होती है. वहीं मंत्री सामने की कतार में बैठते हैं. उनकी सीटें आमतौर पर वरिष्ठता के आधार पर तय होती हैं. विधायक और मंत्री कभी-कभी आपसी बातचीत के लिए अपनी सीट बदल लेते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का अपनी निर्धारित सीट छोड़कर मंत्री की सीट पर जाकर बैठना सामान्य नहीं था. विजय के सीट बदलने से पहले विधानसभा में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों की गैर मौजूदगी को लेकर सवाल उठा. विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने पूछा कि विभागीय सचिव चर्चा के दौरान सदन में मौजूद क्यों नहीं हैं.

बिग चिल केक्री में निकला कॉकरोच

नई दिल्ली, 28 अगस्त. दिल्ली के खान मार्केट का फैमस कैफे 'बिग चिल केक्री' इन दिनों अपने डेजर्ट्स की वजह से चर्चाओं में नहीं है बल्कि एक वायरल वीडियो को लेकर चर्चा में आ गया है.

सोशल मीडिया पर वायल हुए वीडियो में डेजर्ट रखने वाले डिस्प्ले रेफ्रिजरेटर के अंदर एक कॉकरोच चलता नजर आया. हैरान करने वाली बात ये है कि इस डिस्प्ले में ब्राउनी के साथ-साथ कई केक और डेजर्ट रखे हुए थे. इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों के मन में हाइजीन, साफ-सफाई को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं.

वायरल वीडियो में दिखाई गई घटना पर कैफे की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. इस पूरे मामले ने लोगों के मन में बाहर खाने को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

अमेरिका में हत्याकर भागा, आगरा में अरेस्ट

छह माह से फरार हत्यारे को तेलंगाना पुलिस ने पकड़ा

नवभारत न्यू

लखनऊ, 28 अगस्त. अमेरिका के मैरीलैंड में निकिता गोडिशाला (27) की हत्या का आरोपी अर्जुन शर्मा 15 दिन से अपनी मां के साथ आगरा में कहरई स्थित शंकर ग्रीन अपार्टमेंट में रह रहा था. यह एकता थानाक्षेत्र में है.

तेलंगाना पुलिस उसकी तलाश में लगी थी. सर्विलांस से उसकी लोकेशन मिलने के बाद गिरफ्तारी की जा सकी. मूलरूप से चेन्नई निवासी अर्जुन शर्मा को तेलंगाना पुलिस ने गिरफ्तार किया. उसके खिलाफ इंटरपोल ने नोटिस जारी हुआ था. नई दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किए थे. अर्जुन 15 दिन पहले ही आगरा आया था. वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है. वर्तमान में कोई नौकरी या व्यवसाय नहीं कर रहा था. मृतका के पिता ने हैदराबाद के थाना लल्लागुड़ा में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जानकारी में आया है कि अर्जुन शर्मा और निकिता में दोस्ती थी. एक ही कंपनी में काम करते थे. उनमें रुपयों के लेनदेन को लेकर विवाद हो गया था. आरोप है कि उसने 31 दिसंबर 2025 की रात में निकिता की हत्या कर दी. अर्जुन ने निकिता को साल 2026 के स्वागत की पार्टी के लिए अपने फ्लैट पर बुलाया था. अर्जुन ने निकिता को पूर्व में कुछ डॉलर दिए थे. उसने वह वापस मांगे. निकिता ने अपनी चचेरी बहन सरस्वती को कॉल किया. उसने अर्जुन को रुपये नहीं भेजे. यह रकम निकिता के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी. अर्जुन ने पार्टी कर पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया. बाद में उसने अमेरिका के हॉवर्ड काउंटी पुलिस थाने में निकिता की गुमशुदगी भी दर्ज करा दी. बताया कि निकिता सुबह करीब सात बजे उसके फ्लैट से चली गई.

एक नजर में

एस-400 नहीं खोज पाए पाक जासूस

नई दिल्ली, 28 अगस्त. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत में तैनात एस-400 वायु रक्षा प्रणालियों का पता लगाने के लिए जासूसों और स्लीपर सेल का इस्तेमाल किया था. एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा ने बताया कि पाकिस्तान एस-400 की स्थिति जानने के लिए हर संभव तरीका अपनाने की कोशिश कर रहा था. पाकिस्तानी पक्ष के लिए एस-400 सबसे बड़ी चिंताओं में से एक था. इसे खोजने के लिए एयर इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया. भारत के भीतर जासूसों को तैनात वायु रक्षा प्रणाली की लोकेशन का पता लगाया जा सके. एस -400 रूस निर्मित लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है. भारत ने इसे अपनी वायु सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से आने वाले मिसाइल खतरों का मुकाबला करने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी.

चेन्नई ग्लोबल स्पोर्ट्स सिटी का ठेका खत्म

चेन्नई. तमिलनाडु में प्रस्तावित ग्लोबल स्पोर्ट्स सिटी परियोजना को लेकर बड़ा प्रशासनिक बदलाव सामने आया है. तमिलनाडु स्थित आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उसे तमिलनाडु खेल विकास प्राधिकरण (एसडीएटी) की ओर से चेन्नई में प्रस्तावित परिसर के लिए मिला अनुबंध समाप्त करने संबंधी पत्र प्राप्त हुआ है. कंपनी को इस महत्वाकांक्षी योजना के डिजाइन, इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण यानी ईपीसी कार्य के लिए ठेकेदार नियुक्त किया गया था. अनुबंध का मूल्य 205.89 करोड़ से अधिक था. एसडीएटी के सदस्य सचिव जे. मेघनाथ रेड्डी ने 31 जुलाई 2026 को जारी पत्र में बताया कि लोक निर्माण एवं खेल विकास मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में परियोजना को नए सिरे से तैयार करने का निर्णय लिया गया.

आज का इतिहास

1887 - भारत के एक प्रमुख चिकित्सक और देश सेवक जीवराज मेहता का जन्म.

1904 - अमेरिका के सेंट लुई में तीसरे ओलंपिक खेलों की शुरुआत

1905 - भारत के ख्याति प्राप्त हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म

1914 - न्यूजीलैंड सैनिकों ने जर्मन समोआ पर क़ब्ज़ा किया

1916 - अमेरिकी कांग्रेस ने जोन्स अधिनियम को स्वीकृति प्रदान की: फिलीपींस को मिली स्वतंत्रता

इमरान को मारने की कोशिश में शहबाज

बेटों ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

नवभारत नेटवर्क

इस्लामाबाद, 28 अगस्त. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व क्रिकेट कप्तान इमरान खान के बेटों कासिम और सुलेमान खान ने पाकिस्तान सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. दोनों ने दावा किया है कि सरकार जेल में बंद उनके पिता को मारने की कोशिश कर रही है.

इमरान खान के बेटों ने अपने पिता की सुरक्षा और जेल में उनके साथ किए जा रहे व्यवहार को लेकर चिंता जताई है. उनका आरोप है कि पाकिस्तानी सरकार उनके पिता को लेकर लगातार ऐसा रवैया अपना रही है, जिससे उनकी जान को खतरा पैदा हो गया है. 73 वर्षीय इमरान खान 3 साल से जेल में हैं. अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद उनके खिलाफ कई कानूनी मामले सामने आए. इसके बाद से वह अलग-अलग मामलों में जेल में रहे हैं. इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान, उनकी पूर्व पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ के बेटे हैं. दोनों लंबे समय से पाकिस्तान में अपने पिता की स्थिति और उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर करते रहे हैं. इमरान खान की जेल में स्थिति को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पाकिस्तान और क्रिकेट के बीच इमरान खान को लेकर चल रहे विवाद का भी जिक्र किया गया है. इमरान खान पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे चर्चित चेहरों में से एक रहे हैं. उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने 1992 में क्रिकेट विश्व कप जीता था. बाद में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने. प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद इमरान खान के खिलाफ कई मामले दर्ज हुए.

दान किए 4 करोड़, खाते में 3 रुपये

- राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा चैक बैंक में लगाने पर खुलासा
- चेन्नई की महिला भक्त एस. नागलक्ष्मी ने किए थे दान

नवभारत न्यूज नेटवर्क

लखनऊ, 28 अगस्त. अयोध्या स्थित राम मंदिर के कर्मियों व सेवादारों की सुविधा के लिए चार करोड़ रुपये का दान देने वाली चेन्नई की महिला श्रद्धालु एस. नागलक्ष्मी की शर्त से दान की रकम को लेकर नया पेच फंस गया है.

महिला ने राम मंदिर ट्रस्ट को चार करोड़ रुपये का चेक तो समर्पित कर दिया, लेकिन अब वह चाहती हैं कि ट्रस्ट पहले लिखित आश्वासन दे कि यह पूरी रकम उनकी मंशा के अनुरूप सिर्फ मंदिर के कर्मियों व सेवादारों की सुविधा पर ही खर्च की जाएगी. चेन्नई की महिला श्रद्धालु एस. नागलक्ष्मी पिछले दिनों रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आई थीं. चेक सौंपते समय महिला ने ट्रस्ट के समक्ष अपनी मंशा भी स्पष्ट की थी. उन्होंने कहा था कि चार करोड़ रुपये की यह धनराशि मंदिर के कर्मियों और सेवादारों की सुविधा पर ही खर्च की जाए. इसके लिए उन्होंने ट्रस्ट से लिखित आश्वासन मांगा. हालांकि ट्रस्ट की ओर से इस तरह का लिखित आश्वासन देने से मना कर दिया गया. इसके बाद महिला चेक ट्रस्ट को सौंपकर वापस चेन्नई लौट गईं.

शर्त पर अड़ी दानदाता

ट्रस्ट की ओर से महिला के दिए गए चार करोड़ रुपये के चेक को बैंक में लगाया गया तो खाते की स्थिति को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई. संबंधित खाते में महज तीन रुपये होने की बात सामने आई. इसके बाद ट्रस्ट की ओर से महिला से संपर्क करने का प्रयास किया गया. बातचीत में महिला ने फिर अपनी वही शर्त दोहराई. उनका कहना था कि पहले ट्रस्ट लिखित रूप से यह आश्वासन दे कि चार करोड़ रुपये उनकी मंशा के अनुसार मंदिर के कर्मियों और सेवादारों की सुविधा पर ही खर्च किए जाएंगे. ट्रस्ट से जुड़े एक कर्मचारी का कहना है कि मामले को लेकर प्रक्रिया की जा रही है.

हस्तियों के ट्वीट

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफार्म में ट्वीट किया की इटली सरकार की ओर से, मैं नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड फाइव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती हूँ. एक ऐसे राजा जिन्होंने अपने देश की सेवा बैलेंस, अधिकार और संस्थाओं की गहरी समझ के साथ की, और अपने लंबे शासनकाल के दौरान नॉर्वे और इटली के बीच संबंधों को मज़बूत करने में योगदान दिया.

भारतीय उद्योगपति, राजनीतिज्ञ और समाजसेवी नवीन जिंदल ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. राखी सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि असीम प्यार, अटूट विश्वास और सुरक्षा का पवित्र संकल्प है. ईश्वर से प्रार्थना है कि हर बहन के जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहे. आप सभी के परिवारों में यह त्योहार ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए.

जल-प्रलय

तिब्बत से सटे पिथौरागढ़ में तेजी से सिकुड़ रहे ग्लेशियर, बढ़ता जा रहा खतरा

77 नई झीलों ने उत्तराखंड में बढ़ाई टेंशन

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नैनीताल, 28 अगस्त. नेपाल-तिब्बत सीमा से सटे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में ग्लेशियरों के तेजी से सिकुड़ने का असर साफ दिखाई दे रहा है. उच्च हिमालयी क्षेत्र में 77 से अधिक नई झीलों के बनने वाली है.

कई जलाशय मलबे से घिरे हैं और अत्यधिक वर्षा अथवा किसी भू-गतिविधि की स्थिति में इनके अचानक टूटने का खतरा पैदा हो सकता है. ऐसी घटना से नीचे की घाटियों में तेज बाढ़ आने की आशंका रहती है, जिससे गांवों, खेतों और पनबिजली ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है. कुमाऊं विश्वविद्यालय के डीएसबी परिसर, नैनीताल के भूगोल विभाग के प्रोफेसर देवेंद्र परिहार ने जीआईएस तकनीक की सहायता से वर्ष 1990 से 2022 तक गोरी गंगा बेसिन का अध्ययन किया. अध्ययन में सामने आया कि 1990 में इस क्षेत्र का 30.9 प्रतिशत भाग बर्फ से ढका था, जबकि 2022 तक यह क्षेत्र घटकर 10.99 प्रतिशत रह गया. यानी 32 वर्षों के दौरान बर्फ से ढके हिस्से में करीब 20 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई. अध्ययन में ग्लोबल वार्मिंग और उच्च हिमालयी क्षेत्र में बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप को इस बदलाव से जोड़कर देखा गया है.

प्रोफेसर परिहार के अनुसार, क्षेत्र के 15 गांव त्वरित बाढ़ की दृष्टि से प्रभावित हैं, जबकि 91 से अधिक गांव सक्रिय भूस्खलन और अनियोजित विकास के कारण संवेदनशील हो चुके हैं. बार-बार होने वाली आपदाओं के चलते 25 से अधिक गांवों को आबादी के लिहाज से जोखिम वाली श्रेणी में रखा गया है. जलवायु परिवर्तन पर लंबे समय से अध्ययन कर रहे प्रोफेसर पीसी तिवारी ने बताया कि पश्चिमी हिमालय में तापमान बढ़ने की गति भी चिंता का विषय है. हिमावरण घटने पर गहरे रंग की चट्टानें अधिक सौर ऊष्मा सोखती हैं, जिससे स्थानीय तापीय प्रभाव बढ़ सकता है. बर्फ पिघलने से हिमस्खलन और झील बनने की घटनाएं बढ़ सकती हैं.